P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-6*September-2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

पुस्तकालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

Libraries and National Education Policy 2020

Paper Submission: 10/09/2021, Date of Acceptance: 23/09/2021, Date of Publication: 24/09/2021

शालिनी गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग,
राजकीय जी. एस. कॉलेज,
मुन्गोली, अशोक नगर,
मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

मानव क्षमता को पूर्ण रूप से प्राप्त करके एक न्याय संगत पूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मूलभूत आवश्यकता होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करती है।विश्व मंच पर सामाजिक न्याय और क्षमता राष्ट्रीय एकीकरण, वैज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक संरक्षण के अंतर्गत देश की सतत प्रगति और आर्थिक प्रगति की कुंजी होती है। सार्वभौमिक उच्च स्तरीय शिक्षा वह उचित साधन है जिससे देश में समृद्ध कौशल और साधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज ,राष्ट्र और विश्व की उन्नति के लिए किया जा सकता है। आने वाले समय में भारत विश्व का सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना ही भारत का प्रमुख लक्ष्य होगा। भारत सरकार द्वारा सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 एसडीजी में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी जिससे कि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। रोजगार और वैश्विक परिस्थिति में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह आवश्यक हो गया है कि विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे तो सीखे ही और साथ ही साथ वे सतत सीखते रहे। इस प्रकार विद्यार्थियों में सतत सीखते रहने की कला का भी विकास किया जाना आवश्यक है। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ावा देने के स्थान पर इस बात पर भी अधिक जोर देने की आवश्यकता है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सीखें, विभिन्न विषयों के बीच अंतर को समझ सके,कुछ नया सोच पाए, और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में लाने में सक्षम हो पाए। वर्तमान में एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता है जो विद्यार्थी केंद्रित हो,खोज,जिज्ञासा,अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो जिसमें लचीलापन हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने, समझने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने वाली हो और निश्चित ही मनोरंजन पूर्ण हो।शिक्षा को विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करने वाली होना चाहिए।इसके लिए पाठ्यक्रम में गणित और विज्ञान के अलावा बुनियादी कला,मानविकी, शिल्प, खेल और भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य आदि का अवश्य ही समावेश किया जाना चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा को नैतिकता,तार्किकता,करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए भी व्यक्ति को सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए।2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी भी मामले में पीछे ना हो।शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित शिक्षार्थी को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।

Education is a fundamental requirement for the development of a just perfect society and promoting national development by fully realizing the human potential. Quality education provides universal access. Social justice and competence on the world stage are the keys to the country's sustainable progress and economic progress under national integration, scientific advancement and cultural preservation. Universal higher level education is that proper means by which the best development and promotion of rich skills and resources in the country can be done for the progress of individual, society, nation and the world. In the coming times, India will be the nation with the largest youth population in the world and providing equal opportunities of quality education to the youth will be the main goal of India. According to the Global Education Development Agenda reflected in Goal 4 SDGs of the Sustainable Development Agenda 2030 by the Government of India, the world aims to ensure inclusive and equitable quality education for all by 2030 and promote opportunities for lifelong education. To achieve this goal, the entire education system will need to be

restructured to promote transformation and learning so as to achieve the all-important goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Rapid changes in employment and the global environment have made it necessary for students to learn what they are taught and at the same time continue to learn. In this way, it is necessary to develop the art of continuous learning in the students. Therefore, instead of promoting content in education, there is also a need to emphasize that children learn problem solving and logically and creatively, understand the difference between different subjects, think something new, and learn new information. be able to be used in new and changing situations or areas. Presently there is a need for a learning process that is student-centred, driven by discovery, curiosity, experience and dialogue, which is flexible and enables students to see, understand in a holistic and integrated manner and is certainly entertaining. Education should be a balanced development of all aspects and abilities of students. For this, apart from mathematics and science, basic arts, humanities, crafts, sports and languages, literature, culture and values etc. must be included in the curriculum. should be done. Education should build the character of a person. Education should inculcate morality, rationality, compassion and sensitivity and at the same time should enable the individual for employment. By 2040, India should aim for an education system that is not lagging behind in any respect. The system should be such, where the highest quality education is available equally to the learner belonging to any social and economic background.

प्रस्तावना

प्राचीन भारत में जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, वह उस समय की विश्व की शिक्षा व्यवस्था से कहीं अधिक उन्नत और उत्कृष्ट थी।परंतु कालांतर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरता गया क्योंकि भारत आए हुए विदेशियों ने यहां की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में बढ़ावा नहीं दिया जितना देना चाहिए था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और वर्तमान में भी यह चुनौतियां व समस्याएं हमारे सामने सिर उठाए खड़ी है। मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने के उद्देश्य से वर्तमान भारतीय सरकार ने शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया है।लगभग 3 दशक के बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला साबित होगी।

साहित्वालोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया का आयोजन किया गया था। विभिन्न प्रकार के शिक्षाविदों के अनुभव तथा के. कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा के आधार पर शिक्षा तक सब की आसान पहुंच ,क्षमता,गुणवत्ता, समानता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है।नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वी सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूल और महाविद्यालयों की शिक्षा को अधिक समग्र- लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और विश्व की महाशक्ति के रूप में बदल कर प्रत्येक विद्यार्थियों में अंतर्निहित अद्वितीय क्षमताओं और कौशलों को सामने लाना होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्याय पूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक श्रोत है। तकनीकी रूप से स्वतंत्र भारत में अभी तक केवल दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1968 ईस्वी में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों के बेहतर क्षमता वर्धन के लिए उचित प्रशिक्षण और मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। परंतु ये प्रस्ताव पूर्ण रुप से लागू नहीं हो सके। 1968 की शिक्षा नीति में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक वस्तुओं तथा क्षमताओं के विकास पर जोर देने की बात की गई थी। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की परंपरा के प्रकाश में यह नीति तैयार की गई थी। इसके बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था।अब साल 2020 में यह तीसरी शिक्षा नीति आई है।माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई ।जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई राष्ट्रीय

शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। पूर्व की शिक्षा नीतियों में 10+2 का नमूना अपनाया जाता था परंतु नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का नमूना अपनाया जाएगा। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय जनता पार्टी के 2014 के आम चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल थी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को की गई।सन 1986 में लागू की गई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है।नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा करते हुए कहा कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही तरह का नियामक बनेगा व एमफिल की डिग्री को खत्म किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने अपने बयान में कहा कि डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी मंच बनाया जाएगा। ई-कोर्सेज शुरू में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा और वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी प्रदान की। इस नई शिक्षा नीति का ब्लूप्रिंट इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक कमेटी ने तैयार किया। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी देने की औपचारिक घोषणा की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है।मोदी सरकार ने 2016 से ही नई शिक्षा नीति को लाने की तैयारियां शुरू कर दी थी और इसके लिए टीआरएस सुब्रमण्यम कमेटी का भी गठन किया गया था। जिन्होंने मई 2019 में शिक्षा नीति की ब्लूप्रिंट केंद्र सरकार के सामने रखी। लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आया।इसके बाद सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद और जेएनयू के पूर्व चांसलर के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया।

मुख्य शब्द / Keywords

उद्देश्य, पूर्व में बनी समितियां,मसौदा।
Objectives, committees formed earlier, draft.

स्वतंत्रता के बाद भारत में बनी शिक्षा समितियां

1. डॉ एस राधाकृष्णन आयोग 1948-49
2. मुदालियर शिक्षा आयोग 1952-53
3. डॉ डीएस कोठारी आयोग 1964
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार समिति 1992
5. एमबी बुच समिति 1989
6. जी राम रेड्डी समिति 1992
7. प्रोफेसर यशपाल समिति 1992
8. पारेख समिति 1993
9. प्रो. खेरमा लिंगदोह समिति 1994
10. प्रो.आर टकवाले समिति1995
11. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005
12. जस्टिस जेएस वर्मा समिति
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017

अध्ययन का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

1. शिक्षा प्रणाली में आधुनिकता के मिश्रण के साथ-साथ देश की संस्कृति और अखंडता में सुधार लाना।
2. नई शिक्षा नीति के अनुसार क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा
3. नवीन शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा।
4. तकनीकी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय कला, भाषा और संस्कृति को सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व स्तर पर ज्ञान महाशक्ति बनाना है।

मसौदा

नवीन शिक्षा नीति में नवीन परिपत्र और शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है जिसमें 5+3+3+4 का प्रारूप है। जिसमें आयु और वर्ग के अनुसार 13 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है -।

प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर की शिक्षा में 3 से 8 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है।
इस स्तर पर 3 साल तक की प्री स्कूल शिक्षा तथा 2 साल की स्कूली शिक्षा जिसमें 1 और 2 कक्षा को शामिल किया गया है।

पूर्व माध्यमिक स्तर

इस स्तर में 8 से 11 साल तक के बच्चे आएंगे।जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया है।इस स्तर पर बच्चों को क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी।

माध्यमिक स्तर

कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे इस स्तर में आएंगे। इस स्तरमें बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और उन्हें व्यवसाय परीक्षण के साथ-साथ इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी।

उच्चतर माध्यमिक स्तर

इस स्तर में कक्षा 9 से12 तक के बच्चे आएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थी अपनी पसंद का सब्जेक्ट ले सकेंगे जैसे साइंस के साथ कॉमर्स या फिर कॉमर्स के साथ कला ले सकेंगे।

पुस्तकालय और नई शिक्षा नीति 2020-

किसी भी समाज की उन्नति और विकास के लिए पुस्तकालय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।पुस्तकालय ज्ञान के भंडार होते हैं। विद्यार्थियों में पढ़ने की आदतों को विकसित करने में यह मददगार होते हैं।पुस्तकालय व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होते हैं। सभ्य समाज के विकास के लिए पुस्तकालय आवश्यक हैं। सूचना,संचार और परिवर्तन में पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। पुस्तकालय लोगों के जीवन की उन्नति के लिए एक पठन संस्कृति को विकसित करने में मदद करते हैं। नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों को जीवंत और उपयोगी बनाने पर जोर दिया गया है। नवीन शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी समुदाय और शिक्षण संस्थानों में ऐसी पुस्तकों का समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी जिसमें नि:शक्तजन एवं विशेष शिक्षार्थी भी शामिल है।नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की किताबों तक पहुंच संभव हो और किताबों का मूल्य भी सभी के खरीद सकने के सामर्थ्य के अनुसार हो। निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों में किताबों को गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक बनाना जिससे छात्र उन पुस्तकों को प्रयोग में ला सकें। पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय स्टाफ भी समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। नई शिक्षा नीति में छात्रों को किताबें पढ़ने और घर ले जाकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को भी बताने का अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों और पुस्तकालयों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी आधारित ऑनलाइन किताबें, आईसीटी से लैस पुस्तकालय आदि विकसित किए जाएंगे। व्यापक रूप से पठन और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए पुस्तकालय एवं मोबाइल पुस्तकालय और सामाजिक पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। पठन को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए बुक क्लब सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पुस्तकालय शिक्षण संस्थाओं के दिल हैं और सरकार किताबें,पत्रिकाएं और अन्य शिक्षण सामग्री जैसे पठन सामग्री की खरीद को और अधिक मजबूत बनाएगी। डिजिटल पुस्तकालयों को विकसित करने और पुस्तकालय पुस्तकों की ऑनलाइन पहुंच के लिए कदम उठाए जाएंगे।देशभर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा।नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि पुस्तकालय के आसपास गतिविधियां होनी चाहिए जैसे- कहानी,समूह में पढ़ना ,रंग-मंच, बच्चों के द्वारा लिखी गई मौलिक सामग्री और कलाओं का प्रदर्शन करना आदि। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में लाइब्रेरी को स्थान दिया गया है।पुस्तकालय प्रमुख रूप से एक सेवा प्रदान करने वाली संस्था है और पुस्तकालयाध्यक्षता एक सेवा उन्मुख व्यवसाय है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की सेवाएं पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाती है।आधुनिक युग में कंप्यूटर और सूचना तकनीकी के विकास के फलस्वरूप पुस्तकालय सेवाओं का समग्र स्वरूप परिवर्तित हो गया है। सूचना तकनीकी ने पुस्तकालय की अधिकांश परंपरागत सेवाओं को प्रभावित किया है और इन सेवाओं के रूप को बदलकर पूर्ण रूप से उच्च तकनीकी युक्त बनाया है। ।किसी भी पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं पुस्तकालयों के प्रकार,पाठकों की प्रकृति और पुस्तकालय में रहने वाले संग्रह पर निर्भर करती हैं। अतः उसी के फलस्वरूप पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी अलग-अलग हो सकती हैं जिसके द्वारा हमें विद्यार्थियों को बहुत सारी सेवाएं देनी होगी।एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, स्तरों, भाषाओं, शैलियों में किताबों की उपलब्धता, पहुंच ,गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित

करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी।नई शिक्षा नीति के लिए e-content विकसित करने के लिए भी विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए कस्तूरीरंगन ने कहा था कि वीडियो लाइब्रेरी बनाने की विश्व विद्यालय की योजना निकट भविष्य में नई शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है बल्कि उन किताबों को समझना, विश्लेषण करना, उसका अर्थ निकालना और उसके तात्पर्य को समझना है। एक पुस्तकालय लर्निंग हब जहां सीखने का वातावरण मौजूद है और छात्रों को विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान कर सकता है। नई शिक्षा नीति 2020, पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित बातों पर जोर देता है-

1. संपूर्ण भारत में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालय की स्थापना।
2. विद्यालयों के लिए पुस्तकालयों को समृद्ध बनाया जाएगा।
3. शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए आनंददायक और प्रेरणादायक पुस्तके विकसित की जाएंगी, जिनमें उच्च- गुणवत्ता, अनुवाद (आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता) शामिल है।
4. उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, ब्लैक बोर्ड,कार्यालय, शिक्षा सामग्रियां, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण आदि सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। चल पुस्तकालय और बाल पुस्तकालय खोले जाएंगे।
5. डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।
6. नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी जो भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों की पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुशंसित पुस्तकालयों के संग्रह को समावेशी किया जायेगा।

निष्कर्ष

इस प्रकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति,21 वी. सदी की प्रथम शिक्षा नीति है जिसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास के लिए मूलभूत और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई शिक्षा नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को सहेजते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आवश्यकात्मक लक्ष्य जिसमें एसडीजी 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों में सुधार और उसके पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित रचनात्मक क्षमताओं और कौशलों के विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और औपचारिक ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ उच्च स्तरीय तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संरचनात्मक कौशलों का विकास होना चाहिए वल्कि नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *https://www.hindirhindirwaders.com*
2. *https://www.education.gov.in*
3. *https://www.amarujala.com*
4. *https://www.drishtiias.com*
5. *https://www.hindi.rajras.in*
6. *https://heerubhojwani.com*
7. *An Analysis of new Education policy 2020*